decision But in the Railways the Loco Running Staff and Running Staff as a whole have been forced to work any number of hours even upto the extent of 18/20 hours.

The agreement arrived with All India Loco Running Staff Association for 10 hours duty from signing on to signing off in the year 1973 and announced on the floor of Parliament by the then Minister of Railways, late L.N. Mishra, has not been honoured.

I urge upon the Government to take steps to redress the grievances of Loco Running Staff and Indian Railways.

15.05 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE* DISAPPROVAL OF TEXTILE UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) ORDINANCE, 1983—CONTD.

AND

TEXTILE UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

MR. CHAIRMAN : Now we take up further discussion on the statutory resolution moved by Shri Satyanarayan Jatiya. You have already taken 10 minutes. Please wind up.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मेरी पार्टी के कारण मुझे मौका नहीं मिला है।

सभापति महोदय : पार्टी को टाईम का अलाटमेंट होता है इसलिए इसके मुताबिक दस मिनट भी ज्यादा है। ज्यादा टाईम नहीं मिलेगा।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं महत्वपूर्ण विषय पर जिसका अध्यादेश जारी हुआ था, उसके निरनुमोदन पर खड़ा हुआ हूं। यह डिस्क्रीशन की बात नहीं है कि यहां क्या निर्णय लिया जायेगा। मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा था कि 13 मिलों का अधिग्रहण हुआ है। उस अधिग्रहण के पीछे जो सरकार की नीति और नियत है, वह प्रकट होती है। मिलों का जो अधिग्रहण कर रहे हैं, उनका प्रबन्ध अधिग्रहण पहली शुरुआत है। उसके बाद राष्ट्रीयकरण की बात की जाएगी।

मिलों का जो अधिग्रहण को रहा है, उसमें ध्यान दिया गया है कि लोगों को बेरोजगार होने से बचाया जाए। इन सारी मिलों की देनदारियां बाकी हैं। उन देनदारियों को चुकाने के लिए माननीय वाणिज्य मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आग्रह है जो देनदारिया इन 17 मिलों की बाकी हैं, उसके बारे में आप बतायें कि किसकी जवाबदेही है। 60 करोड़ रुपया एप्लाइज का इन 17 मिलों द्वारा देना बाकी है जिसमें से 50 करोड़ रुपया रुई सप्लाई करने वालों को बाकी है। उनका क्या गुनाह है कि उनको अपनी रुई का पैसा आज तक नहीं मिला है। अब इन मिलों को सरकार चला रही है। सरकार का नैतिक दायित्व है कि इन देनदारियों को चुकाए। पिछली बार 112 मिलें एन० टी० सी० के अन्तर्गत लाई गई थीं। उन मिलों का देनदारियां आज तक चुकाई नहीं गई हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस नीति में परिवर्तन होना चाहिये। यह सीधा उन लोगों का नहीं है जिन्होंने माल सप्लाई किया है। यह ठीक है कि ये मिलें किसी

[श्री सत्य नारायण जटिया]

कारण से बन्द हो गई। क्यों हुई यह भी सरकार को देखना चाहिए। रुई सप्लाई करने वालों, रंग, रोगन, रसायन, मशीनरी सप्लाई करने वालों की सारी बकाया राशि को सरकार को चुकता करना चाहिए।

25 करोड़ रुपया वित्तीय संस्थाओं का इन पर बकाया है। इसको भी सरकार को चुकता करना चाहिये। रुई सप्लाई करने वालों ने सांकेतिक विरोध प्रकट करने के लिए काम बन्द किया है। मैं चाहता हूं इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। आपकी नीति और नियत साफ होनी चाहिये। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं।

बीमार मिलों को हम लेते हैं, उनमें पूंजी भी लगाते हैं तो पूंजी लगा कर पूंजी कमाने की बात भी होनी चाहिये, पूंजी गंवाने की बात नहीं होनी चाहिये। अच्छा प्रबन्धक वह नहीं है जो पूंजी गंवाता है बल्कि वह है जो कमाता है। इन बीमार मिलों के उत्पादन को बढ़ा कर, इनमें एफिशेंसी लाकर उनको लाभ की स्थिति में लाना चाहिए। घाटे की स्थिति में कमी होनी चाहिए। मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये। जिन एन० टी० सी० मिलों पर ऋणों की किश्तें बाकी हैं। इनको अदायगी में उनको छूट दी गई है। वह अच्छी बात है। ब्याज चुकाने के बारे में भी सरकार ने उनको छूट दी है। मेरा इसमें विरोध नहीं है। कुछ नई बात बनती है तो इस प्रकार के प्रोत्साहन आपको देने चाहिएं। देश में उर्जा की, बिजली की कमी है। उससे उत्पादन पर बिपरीत असर पड़ता है। सरकार की मंशा है कि डीजल जैनरेटिंग सैट डालकर कैप्टिव पावर प्लांट डाल कर, बायलर्ज को बदल कर, मशीनरी नई डाल कर उत्पादन को बढ़ाया जाए। यह अच्छी बात है। सरकार ने 311 करोड़ और खर्च करने की व्यवस्था की है। यह सब खर्च सरकार तो कर रही है लेकिन इसको भी देखा जाना चाहिए, इसकी भी निगरानी रखी जानी चाहिये कि खर्च ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है।

एन० टी० सी० की जो मिलें हैं उनका पिछला जो परफार्मेंस है उसको आप लें। राष्ट्रीयकृत जो मिलें हैं उन्होंने 1982-83 में 76.62 करोड़ का घाटा दिखाया था और जिनका मैनेजमेंट आपने अपने हाथ में लिया है उन्होंने 17.87 करोड़ का घाटा दिखाया था। 1983-84 में सितम्बर तक स्थिति यह है कि राष्ट्रीयकृत मिलों का घाटा 35.13 करोड़ है और अधिगृहीत मिलों का 10.82 करोड़। ज्यों-ज्यों आप दवा कर रहे हैं मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। ज्यों-ज्यों कर्ज देते है घाटा बढ़ता ही जा रहा है। वह बात नहीं होनी चाहिय।

इस साल दो लाख रुई की गांठों का 'काटन बेल्स' का निर्यात किया जाएगा। क्यों करेंगे ? किस खुशी में करेंगे ? रुई का निर्यात किया जाएगा तो हमारा ही कच्चा माल है वह विदेशों में चला जाएगा।

जब हमारा कच्चा माल बाहर जाएगा तो हमारे देश के उत्पादन की क्या हालत होगी ? इस शताब्दी के अन्त तक देश में जितना कपड़ा चाहिए, 24 हजार लाख मीटर की जरूरत है जब कि हमारा उत्पादन अभी 12 हजार लाख मीटर ही है।

इसको दुगना करना पड़ेगा और इस हालत में अपने देश में यदि अपने माल की खपत नहीं कर सके तो कैसे काम चलेगा ? हमें तो "फिनिश्ड प्रोडक्ट" को एक्सपोर्ट करना चाहिये ताकि विदेशी मुद्रा मिले और किसानों को भी कपास की कीमत का अच्छा लाभ मिले।

विदेश व्यापार की पिछली हालत देखिये। 1980 में 206 करोड़ का निर्यात किया, 1981 में 184 करोड़ 1982 में 160 करोड़ और जनवरी से मार्च 1983 तक 49 करोड़ का निर्यात किया है। यह 'डाउनवर्ड ट्रेंड' है। विदेश व्यापार में तो मुनाफा हो तभी काम चलेगा। मिलें ठीक चलें और मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए। उनकी भविष्य निधि का हिसाब ठीक से रखा जाय। लेकिन होता यह है कि मजदूरों का भविष्य अंधकार में रहता है, मिल मालिक भविष्य निधि में अपना हिस्सा जमा नहीं करते हैं। ई० एस० आई० का काम भी बेकार है, उसमें भी सुधार करना चाहिये। इसलिये मैंने कहा था वाणिज्य उद्योग में श्रम और पूंजी की जरूरी है साथ ही मजदूरों की बेहतर स्थिति की तरफ भी ध्यान चाहिए और किसी को तालाबन्दी की छूट नहीं होनी चाहिए। तालाबन्दी से उपभोक्ता और मजदूरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

कल मैंने कहा था हमारे मध्य प्रदेश में एक टेक्सटाइल मिल है उसको 'होपलेस' किसने किया। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ जमीन उस मिल को अलाट कर दी और यह धारणा बनाई गई कि इस जमीन को बेच कर नई मिल खड़ी हो जाए। जब सरकार को पता था कि मिल बन्द होने वाली है फिर उसको जमीन क्यों दी गई ? उस मिल पर साढ़ सात करोड़ से ज्यादा की देनदारी है। 1 करोड़ 12 लाख बिजली का बाकी है, 97 लाख प्रोवीडेंट फंड का, 1 करोड़ ई० एस० आई० का और 4 करोड़ स्टेट बैंक आफ इन्दौर का ओवर ड्राफ्ट है। इतना घाटा और उस पर तालाबन्दी, यह सारी परिस्थितियां सरकार को देखनी चाहिए। पिछले कई महीनों से लोग परेशान हैं।

विदेश निर्यात के सम्बन्ध में आर०पी० पोद्दार और आर०एल०एन० विजय नागर ने अपनी पुस्तक में जो श्री मदन गौर द्वारा प्रकाशित की है, कहा है ;

"So far as the export orientation of textile industry of India is concerned, the R.P. Poddar Study Team, which visited Europe in 1979 *inter alia* recommended :—

(1) Improvement in the quality of yarn from spinning ;

(2) Installation of wider width looms in replacement of old ordinary looms to manufacture grey cloth upto 112" width.

(3) Installation of rotatory and wider width processing machinery."

(4) Training of weavers for producing faultless cloth."

और ऐक्सपोर्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चर के लिए जो उन्होंने कहा है :

"A technician to be invited from abroad to set automatic looms to produce fabrics without double picks and lashing picks."

1980 में श्री मेहरा ने अमरीका का दौरा किया था, उसमें उन्होंने उत्पादकता

[श्री सत्य नारायण जटिया]

बढ़ाने की दृष्टि से अपनी अनुशंसा में कहा है :

"The team, therefore, recommended that the industry should be allowed to expand the capacity and machinery, particularly prepartory looms and printing both new and second hand, should be allowed to be imported freely and that procedural formalities should be simplified."

विदेशों से जो मशीनों का आयात किया जाता है, उसमें आयात की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चाहिए। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो 13 मिलों का अधिग्रहण किया है, उनकी देनदारियां क्या है, मन्त्री महोदय अपना उत्तर देते हुए अवश्य बतायें। पिछले वक्त यदि देनदारियों को चुकाया नहीं हुआ है, तो उसको सुधारने के लिए सरकार के यह उचित अवसर है।

मिलो का अधिग्रहण करने की दृष्टि से जो योजना बनाई गई है, जो करोड़ों रुपया खर्च होने वाला है, वह पैसा ठीक से लगे, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। मजदूरों की वेतन, सेवा-सुविधा, बोनस आदि और आवास की सुविधा के बारे में भी साथ-साथ सोचना चाहिये।

एन०टी०सी० के मिलों के कार्यकरण के बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है कि घाटा क्यों होता है। जो आपके सुझाव हैं, वह अच्छे हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन की दृष्टि से क्या आप करते हैं, यह देखने की बात है।

अन्त में अपने निरनुमोदन के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"This House disapproves of the Textile Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1983 (Ordinance No. 10 of 1983) promulgated by the President on the 18th October, 1983."

Now, the Minister will move the Bill.

THE MINISTER OF COMMERCE AND SUPPLY (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : Sir, the Textile Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1983, was promulgated on 18.10.1983 as a consequence of which the management of 13 textile units has been taken over.

There were thousands and thousands of workers employed for quite some time. The financial conditions of these units were in a bad shape even before this strike. Large sums of money of financial institutions were invested in these mills; production has gone down. So, to save the investment of the financial institutions, to save the employment of the workers, to provide an occasion for further investments, the Government came to the conclusion that it is necessary to take over these mills. and once it came to this conclusion, it was necessary so that further frittering away of resources is not done or other things are not done to fritter away the assets; it was incumbent on us to take over their management immediately.

These are, in short, the circumstances under which the Ordinance was promulgated. I would now request that this august House take this Bill into consideration which will replace the Ordinance.

Sir, I beg to move :@

"That the Bill to provide for the taking over in the public interest of the management of the textile undertakings of the companies specified in the First Schedule pending nationalisation connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill to provide for the taking over in the public interest of the management of the textile undertakings of the companies specified in the First Schedule pending nationalisation of such undertakings and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

*SHRI ERA MOHAN (Coimbatore): Hon Mr. Chairman, Sir, on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam I wish to make my suggestions on The Textile Undertakiugs (Taking over of management) Bill, 1983 which has been introduced by the Hon. Minister of Commerce and Supplies. I have been elected to this House from Coimbatore which has about 103 textile mills in which the largest number of workers in the country are employed. I am closely and intimately acquainted with the problems confronting the textile workers. I am also personally aware of the impediments and hurdles faced by the textile mills in their day to day working. With this background I make bold to give a few suggestions on this commendable legislative effort of the Government. The management of 13 sick textile mills in Bombay was taken over by the Government on 18.10.1983 through a Presidential Ordinance. This Bill seeks to substitute this Presidential Ordinance.

On behalf of my party and on my own behalf I welcome wholeheartedly this Bill, as this will ensure continued livelihood for thousands of workers in these 13 sick mills. The acquisition of management of these 13 textile mills will lead to their efficient management. In other words, this Bill caters to the public weal and hence this laudable legislative attempts has to receive unanimous encomium of this House.

I would like you to have a look at the first schedule of this Bill, which contains the names of textile mills whose management has been taken over. Tata Mills, two Podar Mills, three Kohinoor Mills, Finlay Mills and the other textile Mills which were under the management of renowned industrialists reported sick and thousands of workers were apprehensive of their imminent closure. While the other industrial ventures of these industrialists are working profitably, only these textile mills became sick. It will not be far from truth to assert that the funds from the textile mills were diverted to their other industrial ventures. The Government acknowledges the mismanagement of these mills. We have the Company Law in force and all these are public limited companies. This kind of mismanagement should have attracted the provisions of Company Law and the authority of the Company Law Board. I would like to know what action has been taken under the Company Law against these undertakings for such blatant mismanagement. The Hon. Minister of Commerce in his reply to the debate should refer to the action initiated against the former management for violations of Company Law.

Similarly, these mills have received substantial financial assistance from the central public sector financial undertakings. The representatives of financial institutions are also on the Board of management of these undertakings. I am constrained to say that they are equally responsible for such mismanagement. It is their bounden duty to apprise the Government on time the

@Moved with the recommendation of the President.

*The Original Speech was delivered in Tamil.

[Shri Era Mohan]

deteriorating conditions of working of of these Mills. I would like to know what action has been taken by the Government against them for their failure to ensure efficient management of these institutions.

MR. CHAIRMAN : There is long list of Members wanting to speak. Kindly conclude, Mr. Mohan.

SHRI ERA MOHAN : Sir, I come from Coimbatore, known as the Manchester of India with the largest number of textile mills. Please give me five minutes more. I have just started. While I welcome the taking over of 13 textile mills in Bombay, I wish to inform the Hon. Minister that there are several textile mills in Coimbatore which are remaining closed for years and for months together. Thousands of workers have been exposed to starvation and other privations of no small magnitude I will give the names of a few textiles which are sick—S.R C. Mill in Triupur, Padma Mills, Janardhana Mills and Tamil Nadu Spinning Mills in Coimbatore and Anglo-French textile mill in Pondicherry. The B & C Mill in Madras is also on the verge of closure inspite of massive dose of financial assistance from the Government. The workers are frightened of their future livelihood. The Government of India should take over forthwith the management of these textile mills remaining closed in Triuppur and Coimbatore. If this is not done immediately, the industrial unrest will go out of control and the Government of India will be solely responsible for any untoward cousequences. I would compare the situation to the erupting volcano and any time the lava of frustration of workers will envelop the nation. I take this opportunity to warn the Government of violence consequence of inordinate delay in taking over the management of these sick textile mills in Coimbatore.

In today's newspapers you will find the news item that during the past 10 years the NTC Mills have incurred a total loss of Rs. 425 crores. While the NTC mills in southern States are working profitably, the NTC mills in northern States are working under loss. I would request the Hon. Minister to find out the reasons for continued loss of NTC Mills in northern States.

MR. CHAIRMAN : You have taken much more time. Please conclude now.

SHRI ERA MOHAN : A sum of Rs. 266 crores has also been injected for modernising the NTC Mills. I would take this opportunity to urge upon the Minister that substantial funds should be earmarked for the modernisation of NTC mill in southern States which are working well and earning profits. According to my assessment, the NTC Mills incur losses primarily because of the outdated machinery, which are a century old. There is imperative necessity for modernisation. The other primary cause is that the genuine demands of the workers are not resolved on time, resulting in production loss. I suggest that the management should find prompt solutions to the legitimate demands of workers. Again, the substandard cotton is purchased by the NTC Mills; this leads to production of substandard cloth and yarn. This also needs to be looked into.

MR. CHAIRMAN : Please conclude, MR. MOHAN. You need not take any other point. If you do that you will take more time.

SHRI ERA MOHAN : I request the Hon Minister of Commerce to examine the points raised by me and do the needful. In conclusion, I would urge upon the Minister to take over the sick textile mills in Tripura and Coimbatore referred to by me at the outset in the interest of thousands of workers whose cause is dear to the Hon. Minister of Commerce. I extend my full support to this Bill under discussion. I am sure he will not make any distinction between the textile workers

of Bombay and Coimbatore. The Government should take over the textile Mills in Coimbatore and Tiruppur which are closed for years and months together.

*SHRI P. SHANMUGAM (Pondicherry): Hon. Mr. Chairman, Sir, I welcome the Textile Undertakings (Taking Over of Management) Bill, 1983 seeking to replace the Presidential Ordinance promulgated on 18th October, 1983 which vested in the Central Government the management of thirteen textile undertakings in Bombay. This has clearly established our Government's commitment to the cause of workers in the country. This timely action has rescued thousands of textile workers from myriad privations.

I have been elected to this House from Pondicherry where presently thousands of workers—to be precise, 7000 workers and dependents of 40000 families—are on the streets of Pondicherry because of the closure of the Anglo-French Textile Mills Ltd. The Mill was working well under the management of M/s. Ramachari Group. It made a profit of Rs. 110 lakhs in 1979 and again Rs. 41 lakhs in 1980. The situation started deteriorating when the management changed hands in July 1981 to Messrs Jatia and Somani Group.

The exports dwindled from Rs 840 lakhs in 1980 to Rs 607 lakhs in 1982. The Government supplies declined from Rs. 319 lakhs in 1980 to Rs. 252 lakhs in 1982. The Compny's sundry credits are of the value of Rs. 280 lakhs, 50% of which are pressing credits and statutory liabilities. The preference shares of the face value of Rs. 18 lakhs are due for redemption on 31st December, 1983.

At the start of the season the Company had entered into contracts for the purchase of 12,000 bales of cotton at quite a low price, but the constraints of resources have compelled the Company not to execute the contract. The suppliers are threatening to close the deal and cancel the contracts. The paucity of funds has prevented the Company from purchasing basic raw material and other essential raw material.

Till 1979 the former management had maintained the norm of 4% ratio between the interest and the sales turnover. Presently it is a little above 7%. With a view to running the Mill the present management asked for a financial commitment of Rs. 1 crore from the Government. The promoters' contribution is Rs. 35 lakhs and the remaining 65 lakhs would be provided by the lead banks. The present management was to release Rs. 10 lakhs immediately as a portion of the promoters' contribution and the UCO Bank and the Indian Bank to release respectively a sum of Rs. 25 lakhs each, to be followed by the revival of the credit facilities to the tune of Rs. 25 lakhs by UCO Bank. But the present management has not so far contributed its share of Rs. 10 lakhs as the first instalment.

Consequent to the closure of the Mill, it was decided in consultation with the Trade Unions, among other things, to advise the Rodier Mill Cooperative Society to supply ration on loan basis to the workmen until the position in the Mill improved. However, it is learnt that an amount of Rs. 14 lakhs was due upto June 1983 to the Cooperative Stores and Credit Society from the management. It appears that the mill management has collected the dues from the workers, but has not remitted the same to the Society. The concerned Societies are not having any working capital now, they in turn are not in a position to procure the provisions and other essential goods for from other merchants. Consequently, they have also expressed their inability to supply provisions or ration articles to workers on

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri P. Shanmugam]

loan basis any further. It is a question of misappropriation of workers' funds by the present management, which is a very serious charge. The Mill management is also in a huge arrears to the Electricity Department, Pondicherry, to the tune of about Rs. 26 lakhs upto the end of June, 1983. The wages have been paid belated from April, 1983 onwards. Salary for the month of June 1983 and thereafter has not yet been paid.

The present management with a view to rehabilitating the mill submitted proposals in broad terms for additional working capital to be made available at nominal marginal modernisation loan from term lending institutions. The financial institutions are finding it difficult to extent financial help as they are apprehensive that that asssistance would also go down the drain.

As a result of the closure of the Mill, there are daily demonstrations outside the precincts of the Mill and also in other parts of the town. This contagion of industrial unrest is slowly enveloping the whole city of Pondicherry and if is allowed to continue it is quite likely that the workers in other indugtrial units may also join the fray as a sympathetic gesture, Then the Government will have to handle a major labour problem in this small Union Territory.

It is therefore necessary and it is high time that the Central Government interferes in this matter and takes over the management of this mill to give succour and sustenance tn 7000 workers and the dependents of 40000 families. I welcome this Bill which gives legislative sanction to the taking over of management of 13 textile mills in Bombay. Here I would like to point out that the NTC mills in southern States are working well and making profits. Hence there need not be any hesitation on the part of the Central Government to take over the management of Anglo-French Textile Mill in Pondicherry immediately, which alone will save thousands of workers from decimation. With these words I conclude my speech.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति जी, सरकार के काम करने का जो तौर-तरीका है वह संसदीय नहीं है। यह चर्चा पहले भी हो चुकी है। माननीय मन्त्री महोदय ने इस बिल में लिखा है कि इन 13 टेक्सटाइल मिलों को लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि इनकी हालत दिन प्रति दिन खराब होती जा रही थी। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की जो आदत बन गई है, हर बड़े काम को, अच्छे या बुरे काम को अध्यादेश के द्वारा करने की, उसका क्या कारण है ? 18 अक्तूबर, 1983 को जो अध्यादेश निकाला गया उसके ठीक एक महीने बाद संसद का सत्र शुरू होने जा रहा था। अध्यादेश के बजाए संसद को विश्वास में लेकर फैक्ट्रियों का अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया ? सरकार की संसदीय प्रणाली को इन अध्यादेशों के द्वारा कमजोर करने की योजनाबद्ध साजिश है। जब संसद सत्र शुरू होने जा रहा है तो हर बड़े काम को संसद के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह मैं मांग करता हूं। इस बारे में पहले भी चर्चा की गई है। हर बार यही तर्क दिया जाता है कि जनहित में यह काम किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जनवरी 1982 से लेकर बम्बई में मजदूरों की स्ट्राइक होती रही, लाखों मजदूर भूखे मरते रहे, सदन ने बार-बार मांग की कि कम्पनियों का अधिग्रहण क्यों नहीं किया जाता। मजदूरों को वेतन नहीं मिला, बोनस नहीं मिला, उस वक्त इनका अधिग्रहण नहीं किया

गया। मेरा आरोप है कि यह सरकार की उन पूंजीपतियों के साथ साजिश थी। उस वक्त पूंजीपतियों को घाटा था क्योंकि मार्केट में कपड़े की कमी नहीं थी। ज्यादा प्रोडक्शन करने से घाटा बढ़ सकता था। इसलिए अधिग्रहण नहीं किया गया और स्ट्राइक को लम्बा खींच कर मजदूरों को परेशानी में डाला गया।

आज सरकार अरबों रुपया घाटा उठाकर भी इनका अधिग्रहण कर रहा है। अरबों रुपया इसके आधुनिकीकरण पर लगेगा। स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगले चार सालों तक घाटा होगा, उत्पापादन कम होगा। मैं जानना चाहता हूं कि जब माडर्नाईजेशन कर रहे हैं इसके बाद भी कह रहे हैं कि अरबों रुपए का घाटा होगा। आप कृपया कारखानों का कम्प्लीट माडर्नाईजेशन होने से पहले इनको मत चलाइये वरना घाटा ज्यादा होगा। मजदूरों को चाहे वेतन दे दीजिए मगर मुल्क की इकानामी को डिस्टर्ब मत कीजिए। आप मजदूरों को गारन्टी दीजिए कि मजदूरों को पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। उनकी रुकी हुई तनख्वाहों को दिया जाएगा और जिन मजदूरों को निकाला गया था उनको वापिस रखा जाएगा। सदन को विश्वास दिलाना होगा कि आप मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं।

इसमें यह भी बताया गया है कि सस्ता कपड़ा वितरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस बारे में सुझाव देना चाहता हूं कि इस मुल्क में बढ़िया और अच्छे कपड़े, टेकीकाट, टेरीलिन की कमी नहीं है। इन मिलों में इस स्तर का कपड़ा बनाया जाना चाहिए जो इन्टरनेशनल मार्केट में जा सके।

इन्टर नेशनल मार्किट में कम्पीट करके विदेशी मुद्रा कमा सकें। 52 प्रतिशत लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं। टेरीकाट, टेरीबूल और दूसरे अच्छे कपड़े बना कर इस मुल्क के लोगों को लूटने का काम मत कीजिए। आप फारेन टैक्नालाजी पर माडर्नाईजेशन इस उद्देश्य से करें कि इंटर नेशनल मार्किट में, जो कपड़ा पैदा होगा उससे विदेशी मुद्रा कमायेंगे। आपने अपने फाइनेंशियल मेमोरेन्डम में कहा है कि इन्डस्ट्रीयल को तीस हजार रुपए पर-एनम देंगे। आपने इसमें स्पष्ट रूप में नहीं कहा है कि यह पांच, दस या बीस साल के लिए देंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है? आपने जो यह तीस हजार रुपये देने का निश्चय किया है यह किन आफिसर्स की रिपोर्ट पर किया है और अगर देंगे तो कितने वर्षों तक देंगे इसके बारे में नहीं बताया है।

जिन कैपिटालिस्ट्सक ने इस मुल्य में आर्थिक संकट खड़ा किया है आप फिर उनको रुपया देने जा रहे है। मैंने कल भी कहा था कि ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। इनको फाइनेंशियल इंस्टीटयूशन्स से पैसा नहीं मिलना चाहिए। आप इतना पैसा देकर के उनको प्रोत्साहन देते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। पूंजीपतियों को करोड़ों-अरबों रुपया दिया जाता, वे उसका मिस-यूज करते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस मामले में स्ट्रीक्ट्नेस करनी चाहिए। जो इन्डस्ट्री को सिक करे उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही करें। ब्लैक-मनी आज हिन्दुस्तान में पैरेलल इकोनोमी है। उसका मुख्य कारण यह है कि आज कारखाने बन्द हो रहे हैं। कारखानों का जब उत्पादन बढ़ता है तो उसका प्राफिट मजदूरों और सरकार के पास न जाकर कैपि-

[श्री जगपाल सिंह]

टालिस्ट्स के पास चला जाता है। इस पर आप अवश्य नजर रखिए। आपने एक अरब चालीस करोड़ रुपए का घाटा बताया है। इसको कैसे पूरा करेंगे? आप आधुनिकीकरण के नाम पर पैसा लगाये जा रहे हैं। आप संसद को गुमराह कर रहे हैं। मेरा आरोप है कि हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों के साथ सरकार को साजिश नहीं करनी चाहिए चाहे स्ट्राइक, लाक-आउट या प्रोडक्शन कम करने का मामला हो। आपके ब्यूरोक्रेट्स अरबों रुपया कमाते हैं इन्डस्ट्रीयलिस्ट को रुपया देने के नाम पर लाक-आउट कराने के नाम पर। एन०टी०सी० की जितनी फैक्ट्रीयां हैं, उनका आधुनिकीकरण कीजिए। वह सरकार के हाथों में हैं। मेरे इलाके सहारनपुर में भी फैक्ट्री है। वहां भी काफी घाटा हो रहा है। इस लिए इन फैक्ट्रियों की कन्डीशन को आप सुधारिए।

आपने इस बिल के एम्ज एन्ड आबजैक्ट्स में लिखा है कि अगर इनको न लिया जाता तो इसकी भयानक प्रतिक्रिया हो सकती थी देश में। आज तक स्ट्राइक्स कारखानों में होती रही है, फैक्ट्रियों में होती रही है तब मुल्क में कोई उसका सीरियश रिएक्शन नहीं हुआ और सदन के बैठने से पहले अगर आपने इन मिलों का अधिग्रहण नहीं किया होता तो कोई सीरियस प्रतिक्रिया होती देश में, इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सरकार को अरबों-करोड़ों का घाटा मिलों में जो उसने ली है हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वह घाटा बन्द हो। साथ ही मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि देश के कैपिटलिस्ट्स के अधीन जो मिलें या फैक्ट्रियां चल रही हैं उनको बजाय प्रोत्साहन या इनाम देने के, वे ठीक से चल सकें, उनकी स्थिति सुधर सके। इसके लिए आपको सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम इन कारखानों की दशा सुधार नहीं पाएंगे। हिन्दुस्तान के जो प्राइवेट कैपिलिस्ट हैं उनकी मिलों से भी ज्यादा बुरी हालत उन मिलों की है जो आप ने हाथ में ले रखी है। मैं चाहता हूं कि प्रोडक्शन पर, रौ-मैटीरियली पर, मशीनरी के आधुनिकीकरण पर आप सीरियस सोचें और सोच कर इनको चलाने का आप काम करें और हमेशा ही आपके सामने मजदूरों का हित सर्वोपरि होना चाहिए।

SHRI BALKRISHNA WASNIK (Buldhana): Mr. Chairman, Sir, I rise to welcome the step taken by the Government in take-over of the thirteen Bombay Textile Mills. Sir, it is long overdue. There was a demand from the workers' union Rashtriya Mazdoor Sangh as also by Government of Maharashtra to take over these mills. After a long time, the Government has taken over these mills.

As everybody knows, there was mismanagement and more than 35,000 workers were involved who had to be given the work. And for this very reason; the Government has taken over all these mills. Not only 35,000 regular workers were involved but, I am told, there were 45,000 *badli* workers also. It was a question of not only 35,000 workers but it was a question of providing jobs to nearly 80,000 workers. Government has taken this wise step to do it.

A member from the Opposite side has said that this should have been done during the session time but, I think the Government has done the right thing. Had any time or notice

been given to these mill owners, I do not know what they would have done. They are known for many things. All those tricks they might have played not only on the mills, on the workers but also on people of this country and on the nation as well. It was a right thing that Government has taken this action very swiftly and their takeover was complete during the few hours in the night.

Sir, I was glad to note that Government was considering to organise another Corporation for these Mills. I do not know if they are having second thoughts. The record of the National textile Corporation which is at present going to run these Mills—it is running to many other mills already—is not very happy and, I am sure, the Government are also not happy about the way in which the National Textile Corporation is working.

The N.T.C. has been showing a declining trend during the past few years.

Last year there was further decline. I don't think that only by taking over a few mills this chronic problem of sickness in the textile industry will get solved. I say not only the industry but also the trade in yarn and trade in selling the cloth has also to be under the public sector. Unless all these three things are in public sector there cannot be a good policy which can be executed in a rational way in the interest of the nation.

Sir, the NTC is incurring loss after loss. During the financial year 1981-82, the aggregate loss was to the tune of Rs. 73.20 crores. I do not know if at any time in the near future the NTC is going to make any profit. The yarn trade is in the private hands. They are giving no help to these mills. On the other hand they are creating many impediments. Also when the NTC goes to the market to sell the cloth there is difficulty faced by them and the one thing that the Janata Party government did has, I think, led to the difficult situation. It was during the Janata Party government period that the private monopoly controlled mills got exemption from producing cheap controlled cloth. Now, the NTC mills are responsible for producing 50 per cent of the cheap cloth. Out of the total of six million meters of cheap cloth the NTC were supposed to produce 355 million metres. The rest has gone to cottage sector. The mills in good condition which were obliged to use 20 per cent of their capacity for the production of controlled cloth are now free from that responsibility and so long as this discrimination is there between the private owned mills and the nationally owned mills, the nationally owned mills cannot make profit and show results. So what ever was done during the Janata party. I think, it is high time for the Government to review the situation and correct this thing. I am sure the Hon. Minister incharge of this Ministry who is very dynamic will take a positive decision in this matter.

Sir, instead of going to other points, I will concentrate on these points only. I request the Hon. Minister to take note of these points.

With these words I conclude.

SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South) : Mr. Chairman, Sir, we are discussing a very important Bill. We should discuss it dispassionately and thoroughly. We are discussing the Bill in this background that this Parliament, in the past, in the days of Pandit Jawaharlal Nehru, had supported the basic principle of having commanding height of the economy in this country. And pursuant to that unanimous resolution that was adopted at that time, Government adopted several measures.

According to these measures, whereever they thought that in the national interest they could take over certain establishments, Government started taking them over.

Against this background, some progress in the direction of nationalisation

[Shri Ratansinh Rajda]

was made. But, at the same time, certain people in this country are posing questions whether it is mere slogan-mongering, whether it is nationalisation for the sake of nationalisation, or nationalisation for the sake of bringing about social and economic justice to society.

So, Sir, from this viewpoint, it is time that we must halt for a minute and ponder over the matter for a while. In this matter of nationalisation, in regard to whatever steps we have taken, have we fulfilled our promise to the people ?

Have we risen up to the occasion ? Have we brought about social and economic justice that we promised to our people ? I am sorry to point out that we have failed the masses and the poor people of our country. We gave high hopes have not borne fruit.

Now, Sir, having said this, I will offer my remarks about the take over of the 13 textile establishments. What is the condition of the textile industry ? Last year 100 million man hours were lost. Government just remained a silent spectator. In the City of Bombay textile strike went on for such a long time. Government could not do anything. Government was docile, impotent, inefficient and helpless to solve the problem and to come out with a proper solution, as soon as the strike was foisted on the workers by labour leaders like Mr. Datta Samanta.

Sir, when Government becomes a silent spectator where can the workers go ? What will happen to the growth of healthy trade unionism in this country ? We have come out with several ideas and one important idea is workers' participation in management. Mr. Wasnik who preceded me was talking about what happened during Janata party regime.

Sir, I do not know what is his logic; I do not know whether he has gone through the records and the facts. Sir, the facts are, that during the Janata regime, a Committee was appointed with regard to workers' participation in management. That Committee's Report was ready within two months. But then the Government collapsed and it could not be implemented.

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : Why was it not implemented within the time that you were there ?

SHRI RATANSINH RAJDA : Government was not there; Government was removed.

PROF. N. G. RANGA : At that time they had not yet gone out of power and they could have taken action.

SHRI RATANSINH RAJDA : Prof. Ranga, you must take a dispassionate view. You are an elder statesman. Let us try to recapitulate the facts. The Janata Party appointed a Committee. That Committe went into the matter and came out with a Report. The Committee's Report was there. These are glaring facts which no one can deny.

Thereafter the government was removed and the new Government had come. The onus of the entire burden fell on you. The ball has been in yonr court. Now, you have appointed a Committee and the report of that Committee is not forthcoming. Six months have passed. I would like to base my question on these points. If you are very serious why don't you go ahead with the workers' participation in the management, etc. ? What have you done so far ? Why are you keeping quiet ? It is no use merely to hurl charges on the Janata Government. The attitude of the ruling party and the Treasury benches is whenever something wrong happens, the stick is quite handy to weild on the Janta party because our Government was there at that time. But the entire country knows about it.

16.00 hrs.

Now, we are talking of sick industry and sick mills. You have been taking over the sick mills. Have you got any cogent and ethical policy with regard to taking over of these sick mills ? Why are you taking over the sick mills alone and why not nationalise the whole textile industry ? The point is whether the Government has got wherewithal. I am prepared to stand by the Government if they are prepared to do so. But I know the Government is incapable of doing it and I do not think that it will just make a jump and reach the highest peak when you are not in a position to jump over a step. This is the position and you should take a practical view.

Now, Sir, I would like to draw the attention of the Hon. Minister to certain manipulations which are going on in the textile mills. Deliberately textile establishments are made sick and the major part of the capital is being diverted for some other purpose. People who have got 4% to 6% share in the establishments earn lots and lots of money and they are deploying the entire capital for other purpose, for their own personal, selfish and family purposes. Then they come out and say that the mills are sick and the Government should take them over. Under these circumstances, I think we must think of these things *de novo* so that we can come out with certain concrete plan as to what we should do under the circumstances. If there are black sheep who are deliberately making the establishments sick with ulterior motives, then Government should not fall a prey in their hands.

Now, Sir, there are certain failures on the part of the Government. Our infrastructural deficiencies are coming in the way. Power shortage is there. When there is power shortage you cannot blame others and the Government has so far miserably failed to improve the position. Whenever the infrastructural deficiencies are there, we must try to remove them. Then the question of lock out also comes. Last year, we had celebrated 'Productivity Year' and it is a sad commentary that during that very 'Productivity Year' our productivity ratio had touched the lowest ebb and we could not increase our productivity. In this way we are managing the affairs of the country. What right do we have to claim that we are on the path of progressive steps ? It is nothing but resorting to slogan-mongering only.

Now; you have been managing certain textile mills aready and most of those mills are running into losses, colossal losses.

The National Textile corporation has been working scandelously. I have raised my voice against it at different levels, including the Consultative Committee meetings. I have been asking for a thorough enquiry about the functioning of the National Textile corporation. It has a scandelous functioning. The corruption is stinking corruption anywhere and everywhere. Certain bureaucrats and certain vested interests have made it their monopoly. A gentleman becomes a director in the subsidiary, next year another gentleman becomes a director, and those four or five people rotate in these posts one after the other. In the case of National Textile corporation at Gujarat crores of rupees were wasted but in spite of that, those corrupt officials were not removed from there. why ? Why don't you put tried and efficient people who have proved their efficiency there ? We must put such people there and tell them that we want results. We must have result-oriented bureaucracy. We must put officers who would get things done. The persons who are blacklisted, against whom there are complaints in the press and the public, the persons who are corrupt, should not be allowed to continue in the National Textile Corporation. If it is done, I think, it would be a great boon for the NTC organisation, the Government and the bublic at large. At present, a large amount of money is being wasted because of corruption.

[Shri Ratansinh Rajda]

I would not stop at that; I would like to give certain constructive suggestions to the Government, if the Government would like to pay any heed to these suggestions. I would like to pose a question, whether the Government have laid down any scientific policy as far as the textile or the cloth to be provided to the poor and the common man of the country is concerned. You can decide that some cloth with particular counts, say fourteen counts, will be reserved for the cooperative sector, for handloom, for khadi. weaving industries, hand-spun. That we are not doing. Crores of people are unemployed; we have got large manpower which is unemployed. Mahatma Gandhi is the only answer, but we are not relying on that. When we cannot provide through machinery enough employment to all the manower, it would only behove us that we take a step in the right direction, and come out with a policy that cloth with some counts would be reserved for the hand-spun, hand-woven and khadi sector etc. Then, something should be reserved for the cooperative sector. Instead of resorting to nationalisation, why not give a filip to the cooperative movement. We must try our hand there. I do not know about the other States much, but in States like Maharashtra, I hear complaints that in the name of cooperative movement, crores of rupees are going down the drain. That should not happen.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : That is cooperative capitalism.

SHRI RATANSINH RAJDA; Even then I can tell you that Maharashtra is in the vanguard; Maharashtra is standing in the forefront as compared to other States, but of course, there are black sheer; at the same time, we have made a great headway as far as the cooperative movement is concerned.

Now, there is a recent trend about the trusteeship. Jiyanand Khira in Bombay or Poona have given away their entire establishment and brought out trusteeship experiment. This is on Gandhian line where the workers are fully participants in the entire management. Management is theirs and all the people put their heads together and thus trusteeship councils are created.

I wonder whether you can try your hand in that. If in that direction we can make a progress, that would be a nice thing. I am told even in London and in the USA now people have started doing it; and I have received reports that there are certain establishments where in on trusteeship experiments they have made a good progress. Of course, here we have not been able to make any progress.

Sir, this Explanatory note that you have given, is completely silent about how many crores of rupees would be required. Rs. 15 crores is the initial amount that has been stated, but it is not the correct amount. I doubt and challenge this figure given is not correct. Already more than Rs. 400 crores have gone down the drain as far as the losses are concerned.

Now, to start these newly taken over establishments, you would require more than Rs. 100 crores. Have you calculated the amount ? I was told in Bombay by somebody who knows the subject that these present thirteen textile mills that we have taken over, would not run at all unless more than Rs. 200 crores are invested. If that is so, I think the Government must come before this House and take us into confidence as to how much amount is to be invested in making the wheels of this industry running.

Sir, I think if efficiency is at the tips of the fingers, if honest officers are kept to run these mills and if certain suggestions that I have stated regarding the khadi industry, cooperative sector and reserving some counts for handloom industry etc. and giving

a play to these trusteeship principles, I think this will be breaking a new ice and we shall be progressing in the new direction.

I hope our dynamic Minister for whom I have got great regard, who means business, shall not tread this only path which is a steriotype approach. I hope he will give up the stereo-type approach and will come out with a fresh mind and show to us that he means business. Then there will be real progress in the textile industry of this country.

16.13 hrs.

[DR. RAJINDRA KUMARI BAJPAI *in the Chair*]

श्री जगपाल सिंह : सभापति जी, अभी खबर आई है और जैसा कि आप जानती हैं कि पिछले दो साल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की स्थापना का....

सभापति महोदय : अभी यह प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कार्यवाही में नहीं आयेगा। आप बैठिये, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बिना नोटिस के नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप यहां पर इस तरह से नहीं बोल सकते हैं आप, बैठ जाइये। हाउस बिना रूल के नहीं चलता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी।

श्रीमती शालिनी पाटिल जो इस सदन की नई सदस्या हैं, अपना पहला भाषण देने जा रही हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए।

श्रीमती शालिनी पाटिल (सांगली) सभापति महोदया, मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। यह मेरा प्रथम भाषण है विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के मन्दिर में मुझे पूर्ण विश्वास है और परमात्मा से मेरी यह प्रार्थना है कि मैं एक लोकसभा सदस्य के अपने कर्तव्य का अपने मतदाताओं के प्रति और राष्ट्र के प्रति संपन्न करने में सदन के माध्यम से सफल हो सकूंगी।

मैं महाराष्ट्र की, विशेषत: बंबई महानगरी की सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं से और परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित हूं। खासकर उस अवधि में जब तकरीबन एक साल की बड़ी हड़ताल हुई थी जो बिलकुल जरूरी नहीं थी, जिसे टाला भी जा सकता था। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। इस विधेयक के साथ हमारे देश की बड़ी और भारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं और जुड़ा हुआ है उनका हल। इस विधेयक का धाराओं के कार्य रूप में परिणत होने पर हमारी बीमार मिलें स्वास्थ्य लाभ करेंगे और उनके डगमगाते कदम सुस्थिर हो जाएंगे। इस विधेयक से चालीस हजार

*Not Recorded.

[श्रीमती शालिनी पाटिल]

कामगारों और उनके परिवारों को भूख से बचाया जा सकेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।

इस विधेयक से 13 सूती कपड़ा मिलें जिनका वर्णन कार्यसूची में किया गया है राष्ट्रीय-करण से पहले सरकार द्वारा हस्तांतरित कर ली जाएंगी। ये मिलें दुर्भाग्यवश सतत कुप्रबंध के कारण वित्तीय चक्रव्यूह में फंस गई थीं। उनका आर्थिक परिस्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वे अपने कामगारों को मजदूरी देने में असमर्थ थीं। उनकी वित्तीय स्थिति इतनी विकट हो चुकी थीं कि हड़ताल से पहले उनकी हालत दयनीय हो गई थीं और हड़ताल के बाद उन पर कोई दो आंसू बहाने वाला नहीं रह गया। वित्त संस्थाएं उन्हें लंबे-लंबे कर्ज दे चुकी थीं जिनका भुगतान और ब्याज का देना भी इन 13 मिलों के ताकत के बाहर था और प्रबंधकों ने देखा और जाना कि जो पैसा बैंकों ने और अन्य कर्जदारों ने इन मिलों में लगाया था, उनके वापिस आने का कोई उम्मीद नहीं था। अब यह देखा गया कि अगर इन मिलों को नवजीवन देना हो तो बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लगाना पड़ेगा। इसलिए जनकल्याण के लिए और उद्योग को टूटकर गिरने से रोकने के लिए और कामगारों और उनके गरीब परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए ये विधेयक एक वरदान के रूप में है। अगर सरकार इन परिस्थितियों में उदासी या असावधानी वरती तो एक बड़ा पाप हो जाता। इसलिए मैं आज श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, केन्द्रीय मन्त्री, व्यापार को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये साहसिक और व्यावहारिक कदम उठाया है जिससे सूती कपड़ा उद्योग का सारा वातावरण ही स्वास्थ्यप्रद हो जाएगा।

इसी सिलसिले में कह देना उचित होगा कि मिल मालिक ये जानें कि ये विधेयक सरकार का निश्चय और उसकी आधारभूत नीति की ओर इशारा करता है। ये हमारी सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है, वे कंपनियां जो कुप्रबंध का शिकार हैं जिनको पब्लिक फण्ड से लगातार पैसा नहीं दिया जा सकता, ऐसे कंपनियों का सरकार द्वारा हस्तांतरण और राष्ट्रीयकरण ही उचित निर्णय है।

मैं विनम्र रूप से मंत्री जी को एक-दो और सुझाव पेश करना चाहती हूं। पहला यह है कि विधेयक की धारा 4 में केन्द्र सरकार ने मिलों की देखभाल करने के लिए महानिदेशक तैनात करने का निर्णय किया है। इस संदर्भ में यह कहना चाहूंगी कि महा निदेशक को इस तरह बढ़ावा दें कि यह बीमार मिलें स्वस्थता की ओर जल्दी से जल्दी बढ़ सकें। हमें यह देखना है कि महानिदेशक उदासीन प्रवृत्ति का शिकार न हो जाएं या अपने आपको लाल फीताशाही में न बहाएं। महानिदेशक को यह निर्देशन देना चाहिए कि इस तरह से काम करें कि प्रबंधकों और श्रमिकों में सद्भाव और शांति का वातावरण रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मिलों का प्रबंध निपुणता और अनुशासन के साथ किया जाएगा। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इस विधेयक के माध्यम से सूती कपड़ा उद्योग का एक साम्राज्य सा सरकार के हाथ में आ जाएगा। अब सरकार को यह प्रमाणित करना होगा कि वो समाज के एक आदर्श मालिक हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मालिक और कामगार

कार्यकर्त्ता जमकर काम करें और इन बीमार मिलों को स्वस्थ मिलों के रूप में प्रस्तुत करें।

मजदूरों की लीडरशिप जब कभी स्वार्थी और गैर-जिमेदार नेता के हाथ में आती है तो मजदूरों पर क्या बीतती है इसका दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव बम्बई की हड़ताल में आया है। मै केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार का अभिनदन करती हूं कि इन्होंने संयम से और प्रशंसनीय रूप से अपने ऊपर अंकुश रखते हुए हड़ताल का मुकाबला किया। इतनी बड़ी हड़ताल भारत के उद्योग के विकास के इतिहास में कभी नहीं हुई और जिस तरह इस हड़ताल को सकुशल सम्भाला गया, जनता इस बात की साक्षी है कि केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार ने स्थिति का धैर्य और बहादुरी से सामना किया। मैं अपना पूर्ण समर्थन इस विधेयक को अर्पित करती हूं।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): Madam, Hon. Minister for Commerce will of course pose the question to the opposition : do you support this Bill or do you not support this Bill ? It is very simple to say because we want him to take over all the textile mills in the country and we believe that there is no future for this Indian textile industry unless the whole of it nationalised. The private owners are reducing it to conditions of complete ruin. So, naturally, since he has not get the courage yet or the will to take over the whole industry, he had decided to take over these 13 mills in Bombay City To that extent naturally, we are welcoming this Bill ; because if he had not taken them over, about 40,000 workers would have been unemployed ; not only 40,000 workers would have been unemployed, but, perhaps Rs 100 crores or so of money of the public financial institutions, which, as usual, has been very generously given to these companies would also have gone down the drain. Perhaps, I do not know, if he has some idea how he is going to recover part of these losses.

His junior colleague, sitting by his side, I find, had given some interesting figures in the other House yesterday in reply to a question ; and he had stated that at present there are 34 textile mills lying closed in the country. After all, all these are manufacturing cloth and cloth is a basic necessity of the people, not the super fine and very highly sophisticated type of cloth, but the basic quality which should meet the necessity of the common people of our country especially those in the rural country-side who, as we know, have a very very low consumption of cloth, one of the lowest in the world, and who require that larger supplies of cheaper cloth should be made available to them. Of course, this responsibility of manufacturing cheap cloth, controlled cloth or standard cloth, as it used to be called, has long ago been divested by this government from the shoulders of the private mills-owners. Now, the whole burden has been put on the mills of the National Textile Corporation. There was time when the government had the good the sense and the courage to insist that the private textile mills should also produce a certain proportion or a certain percentage of their total production should consist of this standard cloth which was to be sold at controlled price. But that is not a profitable venture. The private mills owners did not like it because this did not bring any profit. So, after a certain amount of pressurising and campaining and also they know that the government will succum to it sooner or later, they managed to get the government to release them entirely of this responsibility ; they did not make any standard or controlled cloth. Now, the whole burden has been put on the mills of the National Textile Corporation and nataurally many mills of the NTC are showing losses in their books at the end of the year. I don't say that it is only due to this cause ; there may be other factors also. But one of the factors for

their poor financial working is the fact that they have been loaded entirely with this responsibility of producing the controlled and standard cloth.

About this particular Bill, I would just like to point out that in the preamble it is stated, I quote—

> "whereas by reason of mismanagement of the affairs of the textile undertakings specified in the First schedule, their financial condition became wholly unsatisfactory even before the commencement in January 1982 of the textile strike......"

Here is an admission in black and white that after all the prolonged closure due to textile strike may have aggravated their problems, no doubt but they say that even before the commencement of the strike their financial condition has become wholly unsatisfactory. It is written here in the Preamble of the Bill;

Again, I quote—

> "And whereas certain public financial institutions have advanced large sums of money to the companies owning the said undertakings with a view to makings with said undertakings viable......" etc etc.

Therefore, they now decide to take over these.

My charge against this Government is that nowhere in the country are they bothered with monitorning in any way the growing sickness, the growing instances of this so called sickness in many of these private companies. It does not happen overnight suddenly. One day the company is healthy and 24 hours later it is sick, nobody believes it. It is a long proccss which goes on for a long time and money goes on being pumped into them by these public financial insti tutions. A day will come when these people running these public financial institutions will have to be pulled up by the ear. I do not know what they have been created for—just to donate public fund and public money into the coffers of these unscrupulous and dishonest people ? It is calculated that, for example, in these 13 mills the owners of these mills have got a total investment of not more than Rs. 12 crores. They have made profits over the years of course, many times more than their investment and the public financial institutions have given them more than a hundred crores ; and now they say they are sick. They cannot reopen their mills after the strike. And many of them of course are very big houses, these are all names of big and important houses. I do not went to recount all that. All these names do names which we have been hearing for many many years in Bombay: Elphinstone, Pinlay, Gold Mohur, Kohinoor, Podar Mills, Tata Mills, Shree Sitaram Mills, etc. These are not small people. And who in this country is going to believe that the Tatas did not have enough fund to take care of the needs of the Tata Mills over the years ? Tata is put forward as a model manufacturer of the private sector. He is claimed by you and by his own tribe to be a model employer, model capitalist of the private sector. Who is going to swallow this thing, that in the case of the Tata Mills in Bombay, the Tatas could not have produced enough money to keep these mills running over the years and gradually it became sick and could not function ? I do not think that it shows the Tatas in a very good light. The point is, they have neglected the needs of modernisation ; they have only gone ahead with idea of running, getting maximum profits and they have diverted much of the money they earned out of these mills into more lucrative investment elsewhere. I think Mr. Vishwanath Pratap Singh knows very well this usual story. It happens in the jute mills in West Bengal, this is exactly what they have been doing, taking money out of the mills and investing it somewhere else, nothing about modernisation, doing nothing about the market study or market research and ultimately closing down the mills. A few months ago about twenty jute mills

were closed at one time in West Bengal. Thanks to the Left Front Government, that number has now been reduced to about seven or eight. It is a very precarious situation. Nobody knows; tomorrow again they may close down some mills.

So, what I wish to say is how, is it and why is it so? I hope this does not sound uncharitable. Whatever little bits of welcome I had to say I have said. You should not be sad on that score

Why is it that Government suddenly woke up and showed so much haste and hurry only in the case of these Bombay mills? There are so many mills lying closed. They are not mills, which Mr. Singh will say, are very old mills, in a very bad condition with rickety machinery and with no viability. They are not like that. For example, I think, he knows very well—he will excuse my reminding him—about the Anglo-French Textile Mill in Pondicherry, which is owned by one Mr. Jatiya, who about 10 days back has been arrested in Bombay on the charge of criminal misappropriation. This Mr. Jatiya has got his mill closed for months together. In the course of the representations that we made on behalf of the workers and all that, Mr. Singh has also admitted that this mill has got very good modern and uptodate machinery and this mill has got a very good record of export. They make very high quality cloth, which has a very good export market. It is lying closed. This gentleman was arrested on grounds of criminal misappropriation of Rs. 2 crores or something. Of course, he is out on bail, not like you and me who would not get bail perhaps. But I should have thought that instead of being compelled sometimes as they have been done in the past to take over some very old and non-viable mills—they have had to do it also I know, but here is a mill which is viable, which has got very good machinery, modern machinery and has an export market and everything—why do they not take over such a mill and run it successfully? The workers will cooperate with you. Run it properly and show to everybody that atleast here is one NTC mill which can run well and with profitability in the public sector. The way you are running NTC, you have given the handle to the private sector to say that this public sector is bogus. Not only the private sector but also the public in the country, the workers involved have begun to say: What is this public sector; it is supposed to be superior to the private sector because it is not supposed to run only to be guided by the dictates of this kind of selfish profiteering motive. But the performance of the NTC as a whole is very poor, miserable. Therefore, when we say that other mills should also be nationalised, some people say: What is the use; they will also become part of the sick NTC. So, I should plead with the Government to muster up a little more courage and these 13 mills have attracted their attention not for any economie reasons but for very good political reasons, which I can appreciate because 1.1/2 years of strike, an unparalleled strike, which, of course, was not led by us but led by some other gentleman with whom I may have hundreds of differences, but the workers are workers.

PROF. N. G. RANGA: But they were exploited and misguided.

SHRI INDRAJIT GUPTA: They may be. I do not identify the workers with Mr. Datta Samant. He may be here today. He may go tomorrow. I am not bothered about him. But the workers will remain. The tremendous determination and the unity and the capacity of sacrifice that they have shown in these hard days shows that they were feeling very strongly about their demands and grievances; otherwise, it is not possible for anybody to carry on like this for one-and-a-half years despite all the attempts made from the very beginning to see that strike fails. Everybody was in a very unholy combine—the Central Government, the Maharashtra Government, The Bombay Mills Owners Association and regretably even

the leadership of the RMMS, which thought that its recognition now is in danger. It is the recognised representative body under the BIR Act and to prove that it must see that the strike fails, because the workers had deserted it altogether and gone to Mr. Datta Samant. So from the very beginning everybody was determined that they would never allow any compromise or any negotiation with these people.

They have been taken back to work, I know, on humiliating terms. In many places they have been asked to sign bonds. They have been told to go INTUC office and get a certificate from them otherwise you told them that you won't allow them. If you think that you have got a big victory over the workers-well, I do not think you think like that—really, you are quite nervous because you feel that this experience of 1½ years has isolated your party and your government and your INTUC leadership completely from these Bombay workers. They may lose the strike but they know who are the people who did their best to crush them. Therefore, in order to recover some lost ground—after all, elections are coming some time or other, in Bombay city the textile workers from a very crucial part of the electorate in most of the constituencies at least in North Bombay—so, you thought that the best thing to do now as a sort of gesture, shall I say, or some kind of gammck, is to say that look, our hearts are bleeding for these poor workers now after the strike is over, so, we are taking over these mills. I do not know whether this is actually going to be a first step to full nationalisation, at the moment, it is a management take-over, because we have so many examples. The half-way house which is management take- over between private ownership and full nationalisation, is a mid-way house.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : In doing so do we have political interest or economic ?

SHRI INDRAJIT GUPTA: I think you can have both. The point is sometimes you do not go forward to that you go back again. What are you doing now with these so many non textile companies ? Well, I do not want to go into that because you are not concerned directly with those. After taking over the management, they have been handed over back to other private owners who are willing to buy them. This morning we had an example, during the Question Hour, of one such company. What is happening is......

(Interruptions)

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: There was some news in this morning's newspapers also from West Bengal.

SHRI INDRAJIT GUPTA: So ? This is politics. Your whole attitude is only politics, nothing else. Anglo French Textile Mill is not situated in West Bengal, Laxmi Mill in Beawar is not situated in West Bengal, there are so many other mills. I wish to record again the fact that we are firmly convinced that there is no hope for this textile industry—one of the oldest industries in this country and of which we have been very proud at one time that it should be fully nationalised. This half-way house will not save this industry now. The private owners are no longer interested in this, as in the case of the jute mills. They only want to make some money out of it which they can invest somewhere else and let the basic Industry go to the dogs.

Apart from that, Madam, there are one or two things in this Bill which I would just like to draw your attention to and the main thing there is this clause 5 of the Bill which relates to the payment of the amount which we understand in plain language is compensation but anyway it is not called compensation legally nowadays. It is a payment of amount in cash which is to be given to the management of the textile undertakings for having taken over the

management. Now, a scale of amount is laid down here and it is calculated on a rather unusual basis—(i) for a spinning unit, at the rate of fifty paise per 1,000 spindles or any part thereof; (ii) for a weaving unit, at the rate of one rupee per 100 looms or any part thereof (iii) for a composite unit, at the rate of fifty paise per 1,000 spindles plus one rupee per 100 looms plus one paisa per 10,000 metres of cloth processed in the dye-house ; and so on. All this adds up to something. Members of Parliament are not necessarily expected to indulge in mental arithmatic for the benefit of the Government. I think it is Government's job when they are asking us to vote some money to pay compensation to these gentlemen who have made their units sick. At least you see, if this is the scale on which it is to be given, we must be given details of each of these thirteen mills as to how many spindles they have got, how many looms they have got, how many of them are composite mills ? I believe most of them or all of them are composite mills in Bombay city but there I may be wrong.

Only if we get the full details regarding the number of spindles and looms, then multiply it at this rate of compensation can we work out the total amount which will have to be paid. Why should I do it ?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : It is about Rs. 2,500 per month for all the 13 mills, for 7 lakh spindles and 12,000 looms.

SHRI INDRAJIT GUPTA : You are not much better than I am in arithmetic. Anyway, I think this is a very wrong procedure. It is all very generous of you to come and read from a chit of paper these things. But here is a Bill brought before the Parliament of India.

SHRI CHITTA BASU : It is mentioned here in the Bill that it will not exceed Rs. 30,000 per month.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : It is per annum.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Any way, whether it is Rs. 2,500, or Rs. 250 or even Rs. 25, whatever it is, certainly, I do not think you should pay them a single pie ; that is a different matter. But I am talking about the form, the exact amount, the aproximate amount, which is to be voted by this House for paying these people should be properly and clearly enunciated here, and not in terms of a formula, which it is very difficult to understand. We are not expected to caiculate it after ascertaining the number of looms and spindles and all that.

Then, while calculating the compensatory amount, apart from the question of whether we have to pay them anything or not, should we not take into consideration the amounts which they have taken as loans from the nationalised banks and the public financial institutions, which they have not repaid at all and which they are not going to repay ? Where has the money gone and who has taken it over ? After all, it is public money. They have no further liability to pay back any of the dues ; but, we have to give them compensation now.

Further, we must know how much money they have defaulted from the workers' provident fund and ESI. We know that many of these big units have defaulted to the tune of lakhs of rupees, which they have collected from the wages of the workers as provident fund dues, which they had not deposited, which they had used for their nefarious purposes. Will you mention it in your reply ?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : I will give it.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Please tell us how much they owed to the public financial institutions and the nationalised banks and how much they have cheated the workers of their provi-

dent fund and ESI money deposits. Then only we will get a complete picture.

PROF. N. G. RANGA : It will have to be repaid now to the workers.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : I will mention whatever information I have got.

SHRI INDRAJIT GUPTA : In any case, I would say, though you may not agree with it that, apart from the justification or morality of it, under the present system, where the private sector has to be put on a pedestal and wooed day and night by the Government, for obvious reasons—after all, the elections are coming and funds are required—in this system we cannot expect anything else. So, people are now free to take money from the public financial institutions, put very little of their own money, run the companies, ruin those companies, make them sick and cannot run them, Government steps in, takes it over all the obligations are written off and, perhaps at a later date, they may even be handed over to the same persons, or some brother or nephew of their own in some other name will get the company back.

So, this is not a terribly radical and revolutionary thing which is being done. We must understand the whold context of it. Therofore, Madam, while I am glad that at least my workers are not on the streets, the mills are not reopened, I think, but I suppose they will be reopened soon, they will at least get their jobs and for how long I do not know, but finally I would say that we judge the Government's intentions and their *bona fides* after knowing firstly, what are their plans for the other textile units which are long closed, secondly, for the future of this whole industry as a whole, and thirdly, whether they have got any plan by which all these vast sums of public money which has been looted by these people including the House of Tatas, how this money is going to be recovered. You will see that my welcome is there, but it is rather a qualified welcome I cannot help that. That is the way this system is working.

With these words I conclude.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, इस सदन में और इस सदन के बाहर सब लोग अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि माननीय विश्वनाथ प्रतापसिंह एक सन्त हैं और हमारे विपक्ष के लोगों को ऐसे मुद्दों को रखते हुए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कब और कैसे इन मिलों का अधिग्रहण किया गया। यह निर्णय जो हमारी सरकार ने किया है, मैं समझता हूं कि अपने कर्त्तव्य के प्रति वे ईमानदारी बरतते यदि वे एक निष्पक्ष भाव से जो कदम सरकार ने उठाया है, उसका स्वागत करते।

मान्यवर, कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि देश की जो आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने इन मिलों का अधिग्रहण किया। सवाल यह पैदा होता है कि इस अधिग्रहण की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं समझता हूं कि इस का मूल कारण रुग्णता है और यह रुग्णता आज न केवल प्राइवेट मिलों में है बल्कि एन०टी०सी० की मिलों में भी है। एन०टी०सी० की मिलों में जो यह रुग्णता विद्यमान है, इसके पीछे कारण शायद यह रहा हो कि रुग्ण मिलों को एन०टी०सी० को सौंपा जाता है मगर इस रुग्णता का इलाज क्या है ? माननीय राज्य मंत्री जी ने जो राज्य सभा में उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आज एन०टी०सी०को 426 करोड़ रुपये का

जाता है और 34 ऐसी मिलें हैं जो रुग्ण हैं और बन्द पड़ी हुई है और किसी न किसी तरीके से जिनका अधिग्रहण किया जाना अपेक्षित है। तो मैं माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1968 में जिस उद्देश्य से एन.टी.सी. का गठन किया गया था, वह उद्देश्य एन.टी.सी. पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है। आज एन टी.सी. द्वारा आधुनिकीकरण के नाम पर 226 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि व्यय की जा चुकी है मगर उसके आधुनिकीकरण के बावजूद भी टैक्सटाइल सैक्टर में उत्पादन में बढ़ोतरी का जो लक्ष्य 4.3 प्रतिशत रखा गया था, उसको प्राप्त नहीं कर पाया और केवल 3.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी ही इन वर्षों के अन्दर हो पाई है। इसी तरह से ट्रान्सपोर्ट के मामले में भी जो लक्ष्य रखा गया था, उसकी स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है। उसका लक्ष्य 9.5 प्रतिशत था लेकिन उस के विपरीत 1.3 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि यह जो आधुनिकीकरण एन.टी.सी. की मिलों का हुआ है, यह आई.डी.बी आई और दूसरी एजेन्सियों से कर्ज लेकर हुआ है लेकिन जो फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से पैसा लिया गया है, उसका जैसा सदुपयोग किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया और हमारे माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी ने जो शंका उठाई है, वह ठीक मालूम होती है और मैं भी उस शंका को प्रकट करना चाहता हूं। एन०टी०सी० के मैनेजमेंट से जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा को वह पूरा नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि इसमें वेस्टेड इन्स्ट्रैस्ट्स का हाथ हो और हो सकता है कि पुराने मैनेजमेंट में जो पिछले दर्जे पर लोग काम कर रहे थे वे एन.टी.सी. के टाप आफीशियल्स को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हों।

प्राइवेट सैक्टर हैं, उसमें रुग्णता है। उसके विषय में बड़ी बारीकी से छानबीन किये जाने की जरूरत है। एक के बाद एक मिल पर हमारी पब्लिक सैक्टर की फाइनेंशियल इन्स्टीच्युशंस द्वारा करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी वे रुग्ण हो जाती है और इन रुग्ण मिलों को हमें सामाजिक अपरिहार्यताओं के कारण लेना पड़ता है। हम कब तक इस रुग्णता का शिकार होते रहेंगे, और कब तक एन.टी.सी. पर इन रुग्ण मिलों का हम बर्डन डालते रहेंगे, इस पर हमें सोचना चाहिए। मेरा निवेदन है कि रुग्णता के सम्बन्ध में पूरी स्टडी होनी चाहिए, पूरा सर्वेक्षण होना चाहिए। मैं तो यह समझता हूं कि हाई आफिशियल्स का एक सैल गठित किया जाना चाहिए जो प्राइवेट सैक्टर की मिलों और एन.टी.सी. की जांच करके इस रुग्णता को जड़ से निकालने के उपाय सुझाए। इसके विषय में कार्यवाही होनी चाहिए।

मान्यवर, हमारी सूती वस्त्र सलाहकार परिषदें हैं या उनके नीचे काम करने वाली परिषदें हैं, हमारे निगम हैं, एक तरह कामर्स मिनिस्ट्री तो निगमों का एक पुन्ज ही है। मगर इन नियमों के बारे में लोगों में यह धारणा है कि इनका 'नि' निकल गया है और केवल गम ही गम मौजूद है। हमारी पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, हमारा कंसेप्ट है, वह लोगों में अब बदलती जा रही है। जो लोग पब्लिक सैक्टर के बा नेहरू जी की धारणा के खिलाफ थे आज उन लोगों की हमारे ऊपर हमला करने

[श्री हरीश रावत]

का मौका मिल रहा है। इसका गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है।

हमारा कपडा उद्योग 1978 से संकटग्रस्त है। हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है उसका 20 प्रतिशत हमारे कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि 15 लाख या इससे ऊपर मजदूर सीधे इस उद्योग से सम्बन्धित हैं। परन्तु इसके बावजूद भी जो हमारा योजनान्तर्गत लक्ष्य था, चाहे एन.टी.सी. के क्षेत्र में हो, चाहे प्राइवेट टैक्सटाइल के क्षेत्र में हो, वह राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। उससे हम बहुत पीछे हैं। पीछे ही नहीं हैं बल्कि टैक्सटाईल सैक्टर से किसी भी रूप में हमने जो अपेक्षायें की थीं, उन्हें हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह यू.पी. के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में इन्दिरा जी के नेतृत्व में विकास के लिए मजबूती से काम किया था। मैं समझता हूं कि उसी मजबूती से वे यहां भी कार्यवाही करेंगे, इस कामर्स मिनिस्ट्री, इस टैक्सटाईल सैक्टर में भी कार्यवाही करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे लोग बन्दूक के डाकू थे, ये सन्दूक के डाकू हैं।

श्री हरीश रावत : आप किनके विषय में कह रहे हैं ? (व्यवधान)

मान्यवर हमें कपड़े के टोटल उत्पादन 24 लाख मीटर की आवश्यकता है। आज साधारण आदमी यह कहता है कि कपड़े के मूल्य बढ़ गये हैं। जब उत्पादन घटेगा तो कीमतें बढ़ेंगी। हमें अपने देश में खपत के लिए और अपने अन्तर्राष्ट्रीय आबलीगेशन को पूरा करने के लिए जितने कपड़े की जरूरत है, हम उससे बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं। इससे कीमत तो बढ़ेंगी ही। इसलिए उत्पादन बढ़ाने की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमारे देश के अन्दर प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत दुनिया में सबसे कम है। करीब 13-14 मीटर प्रति व्यक्ति है। हमें इसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारे कपड़ा उद्योग में संकट है और इस संकट के कारण ही उत्पादन कम हो रहा है। न केवल उत्पादन कम हो रहा है बल्कि घटिया हो रहा है। घटिया उत्पादन होने की वजह से हम विदेशों को कपड़ा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपियन कन्ट्रीज को कपड़ा निर्यात करने की जितनी मात्रा निर्धारित थी उतनी मात्रा में हम उन्हें कपड़ा निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे मुल्क हों, वे कपड़े के लिए जापान, कोरिया, थाईलैंड और हांगकांग, यहां तक की पाकिस्तान जैसे मुल्कों की तरफ मुंह ताक रहे हैं और ये मुल्क हमसे कम्पटीशन में आगे बढ़ रहे हैं, वे अपने एक्सपोर्ट आब्लीगेशन को पूरा कर रहे हैं।

उस आब्लीगेशन को वे लोग पूरा कर रहे हैं लेकिन हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि एन०टी० सी० की जो मिलें हैं उन में को रिसर्च-एण्ड डेवलपमेंट विंग होना चाहिए। माडर्न टेकनालाजी के आयात के बारे में प्राइवेट सेक्टर की ओर से भी बराबर दबाव पड़ता है कि इसको ओ०जी०एल० में रख दिया जाए। जो गलत है पर दबाव है, रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के जरिए हमको नई-नई

जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। हमको पता लगना चाहिए कि विदेशों में किस प्रकार की रुचि विद्यमान है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उस रुचि के अनुसार ही उत्पादन होना चाहिए।

सस्ते कपड़े का जिक्र किया गया है। टैक्सटाइल डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों मीटर कपड़ा जो उत्पादित कर रहे हैं उस व्यक्ति के पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है। घर जाकर वह देखता है कि उसके परिवार वालों के पास, गांव वालों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। इसके लिए सरकार ने नीति निर्धारित की है कि हम सस्ता कपड़ा उत्पादित करवाएंगे। इसके लिए पहले प्राइवेट मिलों को मौका दिया गया। मगर प्राइवेट मिलों ने इस काम को पूरा नहीं किया। किसी कारणवश, किसी दबाव में आकर के सारा भार एन०टी०सी०पर डाल दिया गया। अब एन०टी०सी० दबाव डाल कर कीमत इतनी अधिक बढ़ाना चाहता है कि मार्केट में उसी कीमत पर अच्छा कपड़ा मिलेगा तो एन टी सी के कपड़े को कौन खरीदेगा। एन०टी०सी० को 33 परसेंट सस्ता कपड़ा उत्पादित करना चाहिए था। इसके बजाए 11, 12, 15 परसेंट कपड़ा उत्पादित किया जा रहा है। इससे साधारण आदमी की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें सहयोग लिया जाना चाहिए। एन०टी०सी० पर भी इस बात का दबाब होना चाहिए वह अधिक से अधिक सस्ते कपड़े का उत्पादन करे ताकि कामन आदमी, साधारण आदमी की आवश्यकता को हम पूरा कर सकें।

16.57 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

इसके अलावा एन टी सी का अपना मार्केटिंग नेटवर्क होना चाहिए। एन०टी०सी० की पूरे हिन्दुस्तान में अपनी दुकानें होनी चाहिए। आज प्राइवेट लोगों को दुकानें दे दी जाती हैं। जब कपड़े की मांग अधिक होती है और कीमत अधिक मिलती है उस वक्त वे माल नहीं उठाते। इसकी वजह से एन०टी०सी० को भी दिक्कत आती है। इसलिए पूरे हिन्दुस्तान में एन०टी०सी० को अपनी दुकानें खोलनी चाहिएं।

माननीय मन्त्री महोदय से एक आग्रह और करना चाहता हूं कि आपके यहां दो क्षेत्र हैं। एक तो संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के बारे में तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है लेकिन असंगठित क्षेत्र के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा जो वास्तव में संगठित क्षेत्र की कमी को पूरा कर रहा है। इस क्षेत्र को भी इसी तरीके से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फाइबर लूम जो हम बाहर से आयात करते हैं, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि कीमत न बढ़ाएं, ड्यूटी कम की जाये लेकिन साथ-साथ यह भी देखिए कि उसकाप्रभाव पावरलूम या हैन्डलूम पर न हो। हैंडलूम और पावरलूम अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, अधिक समाजोन्मुखी हैं। इस पर कहीं आर्गेनाइज्ड सेक्टर हावी न हो जाए और एन०टी०सी० और प्राइवेट सेक्टर को जो आप लाभ देते हैं उसको कोरनर करने की कोशिश न हो। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

17. hrs.

एक बात जो अभी मेरे मित्र ने कही कि जब तक हम पूरी टैक्सटाइल इन्डस्ट्री को एक नए दृष्टिकोण से नहीं बनाएंगे,

[श्री हरीश रावत]

एक प्रकार का दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकती । आज एक मिल बीमार हुई उसको ले लिया, कल दूसरी बीमार हुई उसको ले लिया, इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। इससे और रुग्णता फैलेगी। इसलिए निवेदन है कि सारी टेक्सटाइल पालिसी को एक बार फिर से देखना चाहिए। दुबारा इस विषय पर विचार करना, अद्योपांत विचार करना जरूरी है ।

चाहे प्रोडक्शन हो या मार्किटिंग या एक्सपोर्ट हमको चाहिए जब तक हम इस पालिसी को रिवाइज नहीं करेंगे और उसके विषय में एक दृष्टिकोण लेकर देश के सामने नहीं आयेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। जो साहसपूर्ण कार्य इन 13 मिलों को उठाकर आपने किया उनके लिए बधाई देना चाहता हूं । अगर ये लोग बम्बई में होते तो पता चलता कि उस रैली में जिस प्रकार से इन्दिरा जी का अभिवादन किया गया, वह अपने आपमें एक प्रतीक था और सारे मजदूर इस बात को समझ रहे थे कि उनका संरक्षण करने वाला कौन है ? कौन बेहतर तरीके से देख सकता है ?इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम 13 टेक्सटाइल मिलों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में जो बिल पेश है, उस बहस में हिस्सा ले रहे हैं। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि टैक्सटाइल इन्डस्ट्री इस देश का सबसे पुराना संगठन है। मेरी जानकारी में इस देश में आठ-सौ टैक्सटाइल मिले हैं। कामर्स मिनिस्टर की जानकारी में कुछ और हो सकती है। इनमें से 103 टैक्सटाइल मिलें टी०एन०सी० द्वारा चलायी जा रही हैं, 9 और उसके हाथ में हैं तथा अब 13 का इन्तजाम सरकार अपने अधिग्रहण में लेने जा रही है, श्री वासनीक जी, श्रीरावत जी और श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी ने बहुत कुछ कहा है। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि टैक्सटाइल उद्योग को अगर आप ढंग से चलाना चाहते हैं तो इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की नीति भी स्वतन्त्र रूप से टैक्सटाइल उद्योग को राष्ट्रीयकरण करने की है। आपको पूरे टैक्सटाइल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए था न कि थोड़ा-थोड़ा करके जैसा कि कर रहे हैं। 13 मिलों का आपने राष्ट्रीयकरण कर लिया लेकिन और मिलें भी तो हैं। उनको भी लिया जाना चाहिए। हमारे साथी श्री राजदा ने कुछ शब्दों में विरोध किया किया और यह कहा कि राष्ट्रीयकरण के लिए हमारे पास अधिकारी नहीं है। दूसरे लोग भी चाहते हैं कि हम नहीं कर सकते। यही अंग्रेज कहा करते थे कि हम हुकूमत नहीं चला सकते इसलिए हुकूमत नहीं आनी चाहिए । लेकिन, ऐसा नहीं है। अगर, नीयत सही है तो राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप में हिम्मत है क्योंकि मेरा आपसे संपर्क रहा है। जब केबीनेट में राष्ट्रीकरण की चर्चा हुई तो कुछ लोग इसके विरोधी थे लेकिन आपने डटकर इसका मुकाबला किया। जो सही बात है, वह मैं आपको बता रहा हूं। आपसे आशा करता हूं कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में गौर करेंगे और पूरे टैक्सटाइल उद्योग को राष्ट्रीयकरण करने की बात सोचेंगे। एम०टी०सी० में भी इन्त-

जाम गड़बड़ है। मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट की जो पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसको पढ़ें और उसकी सिफारिशों पर अमल हो। सबसिडियरी का जो सिस्टम है, उसको अलग बनाइए ताकि प्रबन्ध हो सके।

जो सबसिडियरी का सिस्टम है उसके जरिये आप एन०टी०सी० की मिलों का काम करते है, आप कम से का पांच-पांच और सात-सात मिलों की अलग-अलग से सबसिडियरी बनाएं ताकि मैनेजमेंट अच्छे ढग से चलाया जा सके।

एक विषय की चर्चा उठी थी जो अधूरी रह गई। उस पर मैं जोर देना चाहता हूं। बिल की क्लाज 23 की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह पावर टू टर्मिनेट कांट्रैक्ट्स आफ एम्प्लायमेंट के बारे में है। वर्कर्ज के हित की बात सभी ने कही है। उन्ही के हित में ये मिलें ली गई है। लेकिन उनको एक महीने का नोटिस देकर उनकी सर्विसिस को टरमिनेट करने की बात आप कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिनको आप लायल वर्कर्ज नही मानेंगे उनको एक महीने का नोटिस देकर निकालने का प्रावधान कर दिया है! लेकिन जो कांट्रैक्ट आपने दूसरों के साथ लिए हुए हैं इन मिलों के जरिए, जो पहले से कंट्रैक्ट कैपिटलिस्ट्स ने किए हुए हैं, सप्लायर्ज के साथ, काटन कारपोरेशन के साथ या कपड़े सेठ होंगे उनके साथ, उनके वास्ते आपने इसमें एक क्लाज रखी है:

"Provided that on contract or agreement shall be cancelled or varied except after giving to the parties to the contract or agreement a reasonable opportunity of being heard."

मैं चाहता हूं कि इस पर आप गौर करें। एक तरफ लेबर को एक महीने का नोटिस देकर निकाल देने की बात आपने कह दी है और दूसरी तरफ जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, उनके लिए आपने दूसरा हिसाब रख दिया है। इस पर आप गौर करें।

अब मैं मुआवजे पर आता है। मुआ-में फर्स्ट, सैकिंड और सबसिक्वेंट चार्ज कौन से होंगे इसका कुछ जिक्र नहीं है। इसका जिक्र शैड्यूल में होना चाहिए था। फर्स्ट चार्ज वर्कर्ज वेजिज का, पी. एफ. का होना चाहिए उसके बाद फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंज का होना चाहिए और लास्ट चार्ज कैपिटलिस्ट्स का होना चाहिए, मिल मालिकों का होना चाहिए। लेकिन आपने कहीं शैडयूल में इस तरह की बात नहीं कही है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नेशनलाइजेशन में ऐसा ही रहेगा जैसा आप बताते हैं।

श्री मुश्ताक हुसैन : शुक्रिया।

एक और खतरा है। मेरा सम्बन्ध उस क्षेत्र से है जिसको विकेन्द्रीकृत सैक्टर कहा जाता है, यानी हैंडलूम से है। तेरह मिलों को लेने के बाद उस सैक्टर पर इसका असर पड़ा है। कैसे पड़ा है यह मैं बताता हूं। ये जो मिलें ली गई हैं ये कम्पोजिट थीं। उनमें स्पिडलेज और लूमेज को देखेंगे तो ज्यादातर बाहर से सूत मंगाती थीं—अपने यहां भी बनाती थीं—, लेकिन ज्यादातर बाहर से मंगाती थीं। जब से यह खबर छपी है कि ये मिलें फिर से चलने लगेंगी—पिछले साल यार्न की प्राइस नहीं बढ़ रही है—एक महीने के

[श्री असफाक हुसेन

अन्दर-अन्दर, टेक ओवर की खबर छपने के बाद यार्न की प्राइस, विकेन्द्रित सैक्टर को यानी हैंडलूम सैक्टर को जो यार्न दिया जाता है, एकदम पच्चीस, तीस और चालीस रुपया फी बंडल जो पांच या चार केजी का होता है, बढ़ गई हैं। ये इसलिए बढ़ी हैं कि यार्न की सप्लाई इन मिलों के लिए डाइवर्ट हो गई है। पहले से इन मिलों के आर्डर होंगे, यह अंदाजा होगा कि दूसरी जो स्पिनिंग मिलें हैं साउथ की या बम्बई की, उनकी भी डिमांड होगी। लेकिन सूत के दाम हैंडलूम सैक्टर के लिए जो बढ़ गए हैं, उस पर आप तवज्जह दें और उपाय करें कि हैंडलूम सैक्टर को सूत उसी कीमत पर, मुनासिब कीमत पर मिलें।

यह बात हमारे सभी साथियों ने कही है कि धीरे-धीरे डाइवर्जन करके यह सूती कपड़ा मिलें अब दूसरी तरफ जा रही हैं, और यही कारण है कि बीमार एक तरफ से घोषित कर दी जाती हैं और दूसरी तरफ से हथकंडे अपना करके कपड़ा मिलों में घाटा दिखाया जाता है और इनको सरमाया दूसरी तरफ लगा दी जाती है। आप इन सब बातों से वाकिफ हैं, मैं समझता हूं कि इनके हथकंडों पर भी आपको काबिज होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ बेसिक और बुनियादी बात थीं राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में और इन 13 मिलों के सम्बन्ध में जिनको आपने लिया है उनके सम्बन्ध में मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। आगे आप जब राष्ट्रीयकरण का बिल लायेंगे तो इन पर ध्यान देंगे और जो गड़बड़ियां मैंने पोइन्ट आउट की हैं एन०टी० सी० में उन पर भी ध्यान देंगे। अभी कुछ साथियों ने कहा एक तरफ तो एन०टी०सी० की मिलों में कंट्रोल का कपड़ा बनता है, उसका सारा बोझ उन पर डाला जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि एन०टी०सी० पर यह जिम्मेदारी लादी जाती है तो बोझा हो जाता है, और हैंडलूम के ऊपर जब जिम्मेदारी लादी जाती है तो कहा जाता है कि यह उन पर मेहरबानी की जा रही है। और जो हैंडलूम पर पैसा दिया जाता है सबसिडी का वह एन०टी० सी० से कम दिया जाता है एक ही तरह का कपड़ा बनाने के लिए। हैंडलूम भी आपका है, उससे ज्यादा लोग संबंधित हैं, और एन० टी०सी० भी हमारा है। इन बातों पर ज्यादा ध्यान रखें।

यह चन्द बातें थीं जिनकी ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Barot.

SOME HON. MEMBERS *rose.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will give you all an opportunity...I will call two from this side and two from that side.

Now Mr. Barot.

SHRI MAGANBHAI BAROT (Ahmedabad) : As one having an inherent faita in socialism, I am presumed to support the Bill the Hon. Minister has brought and it necessarily implies my disagreeing with the resolution. First, let me make it clear that my welcome to the Bill is partial—as partial as your action of taking it over is partial.

May I say that the reasons stated by you in the Preamble and if they are what they are—for social justice and

all that, how is it that while either drafting the ordinance... .

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj) : You have no moral justice to be there.

SHRI MAGANBHAI BAROT: How many other closed mills of Ahmedabad which is known Manchester of India...

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hear what he says. Don't see the person. You know there is a proverb—hear what a person says, but don't see the person......*(Interruptions)* No personal reflection at all......*(Interruptions)* Mr. Barot, you don't reply to them. You address the Chair.

SHRI MAGANBHAI BAROT : Sir, I, with great respect, raised the question about the *bonafides* of the Government's actions so far as this Bill is concerned because it is a limited one. I say that my friend, Shri Rawat provided evidence if it was needed that one has to see to believe the impact of the Ordinance in the Bombay meeting of their rally. Does it not prove that, on the eve of this gathering, and, knowing full well that the workers of the Textile Mills of Bombay were going to strongly demonstrate on the arrival of the leaders in that gathering, to appease them and to prevent them from demonstrating the hurriedly called Cabinet Meeting decided this Ordinance ? It hurriedly decided the number of textile mills as well. At the same time, are you not aware that the demand for the reopening of the textile Mills of Ahmedabad was also pending before you and representations were being made ? I may be pardoned to say this because, with this, my sentiments are attached. I am here to-day. I left you with sadness and pain because, I thought that from the workers who elected a candidate of your party relying on the manifesto that each family will be given an employment, you, in fact, snatched away from the workers of Ahmedabad Textile Mills the employment they were having in the Masdern and Monogram Mills. I raised my voice knowing full well that to the party to which I belonged; I must contribute to the philosophy that if the sun shines and if the stars twinkle, and the earth rotates, it is only because of God or Goddess in temple of your party. Believing in leadership I took a five foot photograph of the leader on her birthday on 19th November, expecting thatthe procession of the workers of these closed mills would reach and their voice would be heard by the leader and will be considered. I was proved mistaken.

I ask a question to you. After this Ordinance and, before Parliament opened, did you not, in the usual way of replying, said that the take-over of the Ahmedabad Mills was under consideration ? I can understand that it was under consideration when the Ordinance was brought. But, it cannot understand why, when the Bill was prepared it was not heeded ? I may be pardoned for my language. You did not name the Ahmedabad Mills in the Ordinance. Government lost the grace but in not having added into this Bill, the Government has lost the face. The demand of the workers of Ahmedabad Mills, I feel, is not being considered because, probably, we did not go the way that Bombay workers could go. You may be claiming that you are the draftsman of this Bill. Let me tell you that the Bill is drafted in the blood of the heroic and brave workers of the textile mills of Bombay who gave a heroic fight and did not submit and they prevailed upon you. Ultimately only to appease them, you threw some pieces. This is a compulsion coming from the working class. It has shown once in the history that the working class has the courage to have from the Government howsoever adamant it might be, if it means business, the Bombay Textile Workers under the able leadership of Dr. Datta Samant—one may have a thousand and one differences but show me a single instance in the country or even in the

[Shri Maganbhai Barot]

world, in a democratic country where about 2 lakhs workers in the Mills, even though they were kept open—would say that they would prefer to starve to enter the Mills.

The justification should have been if the entire textile industry had been nationalised. It would have been some compensation.

Sir, I know my time is limited. But, I would like to tell you about the working of the Mills under the National Textile Corporation with which I am associated.

And what your junior said the other day in the other House but the losses ? Please consider how is it that when the production capacity is growing the losses are also growing What is the loss of Rs. 425 crores due to ? Please find a little time and visit mills in Ahmedabad run by NTC. I will take you to a mill. I have a small union there. Your management in the NTC mill was trying to sell as scrap the machinery. Your rule requires that before any NTC mill machinery is to be sold as scrap an inquiry should be made from the other NTC mill whether anyone of them requires it or not. As no such letter was produced inspite of demand by the workers the workers stood like a rock between the greed of the management and machines and did not allow the machinery to be sold as scrap. Then go to Jupiter mill which opened after a heroic fight by the workers. There your management is required to be prosecuted for mis-appropriation but the matter is trying to be hushed up.

In Ahmedabad the four mills which are closed, namely, Monogram mills, Masdern mills, Bhalakia mills and Ahmedabad Manakchand mill were closed due to the mis-management of the management. Please note that on the day before two of these mills were closed, cotton worth Rs. 25 lakhs was purchased but the delivery did not take place in the mills but it was passed on elsewhere. The workers and the vender cried and Rs. 25 lakhs went to the pocket of the management against whom you are not able to raise even in a finger till today.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude.

SHRI MAGANBHAI BAROT ; Please note the writing on the wall that textile industry should never remain in the hands of private management who are plunderers. I want it also not to be given to those of the officers of the NTC who are just a substitute of the plunderers.

Since I am a little associated with workers I wish you to go to any of the NTC mills and you will notice there is not any difference. Ten years have passed. In 1974 we nationalised them. Go to the mills which I have referred to—you will be happy to visit them because the workers there will talk to you in your dialect as they come from U.P.—and you will find there are canteens where no human being can sit and take a cup of tea Canteen has no roof. My six workers were dismissed as they were not sitting in the canteen during the recess in taking their tiffin. The canteen has a capacity of 250 people but 1300 workers are required to finish their meals in half an hour. Therefore, to avoid competition these workers sat in the department and took their lunchand the result was that they were dismissed. Cann't we do something whereby at the entrance of the NTC mill one can make out the difference between the private-owned mill and the Government run mill. In my State, Joint Management Council is a right and workers have right of, participation in management but inquire from yours mills whether your mills are giving any right to the elected representatives of the JMC? Inquire what is the respect of these elected representatives ? Even now you can amend the bill and take over these

four Ahmedabad mills. Earlier two were closed down whose masters are known for invoking all tricks of the trade in the court of law. Take action with firm hand. If you can do something for Bombay workers please do it for Ahmedabad workers. If you, however feel that it could get done only by Dr Datta Samant way then you will have it in Ahmedabad, too But we are known for our industrial relations and peace. We do not believe in striking work and stopping production. We struck work only once when Mahatma Gandhi gave a call in 1942. For six months the workers did not work. That was for a national cause. The Ahmedabad workers did not do it for any selfish interest. Do you want us to learn the lessons from the Datta Samant and make demands in that way? Therefore, I suggest that before you are totally lost from the hearts of the people; you take immediate action with regard to the taking over of these four closed textile mills of Ahmedabad to prove your *Bonafides* and to prove that you are doing it as a matter of social justice.

श्री एम. गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी संजय विचार मंच के जो मेम्बर हैं, उनकी तकरीर सुनी। उन्होंने बहुत अच्छी अंग्रेजी तकरीर की मगर उसमें सब्सटेंस बहुत कम है। बहुत जोश में और बहुत गुस्से में उन्होंने तकरीर की। वे पहले कांग्रेस पार्टी के मेम्बर थे और मिनिस्टर भी थे। अब जबकि वे कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर चले गये हैं, तो कांग्रेस को गाली देना उनका फर्ज हो गया है। इसको ही वे अपना फर्ज मानते हैं और इसके सिवाय और कोई चीज नहीं है। अब यह कहना कि नेशनेलाइजेशन क्यों किया गया है और अब अगर किया गया है, तो इससे पहले क्यों नहीं किया गया, ये ऐसे आर्गूमेंट हैं, जिनको सही नहीं कहा जा सकता। गवर्नमेंट ने जब ठीक समझा, उस वक्त नेशनेलाइजेशन किया और जब नेशनेलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तब वह किया जाता है। नेशनेलाइजेशन इसलिए किया ताकि मजदूरों को फायदा पहुँचे बल्कि देश में जो कपास उगाने वाला किसान है, जो काटन उगाता है, उस किसान का भी भला हो और देश में प्रोडक्शन बढ़े। इसलिए दो-तीन चीजों को दृष्टि में रखकर गवर्नमेंट ने नेशनेलाइजेशन किया है।

अब यह कहना कि दत्ता सामन्त एक बड़े लीडर हैं और अच्छा स्ट्राइक करा रहे हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी भी जगह 5-10 पर सेन्ट लोग 90 पर सेन्ट लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और चाकू दिखा कर, छुरी दिखा कर लोगों को मिलों में जाने से रोक सकते हैं। दिल से किसी ने स्ट्राइक नहीं की है। अगर उनको बराबर प्रोटेक्शन मिला होता और धमकी खत्म हो जाती, तो मिल कभी के खुल गए होते। मिलों में मजदूरों को जाने से जबर्दस्ती रोकना और वायलेंस दिखा कर वहां न जाने देना और फिर यह कहना कि हम बड़े लीडर हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह देखिये कि दत्ता सामन्त कितने बड़े लीडर हैं। जहां पर 80 पर सेन्ट वोटर टैक्सटाइल मिलों में काम करने वाले हैं, वहां थाने से हमारे दत्ता सामन्त लोकसभा के लिए खड़े हुए और वे तीसरी पोजीशन में आए हैं। उस वक्त मालूम हो गया कि उनकी कितनी ताकत लोगों में है। यह कहना कि दत्ता सामन्त ने मजदूरों के लिए कुछ किया है, ठीक नहीं है। अगर उन्होंने कुछ किया है, तो मजदूरों के साथ बेइन्साफी की है और उनकी बरबादी की है। जब हमारे वसंत दादा

[श्री एम. गोपाल रेड्डी]

जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने, तो पहले ही दिन उन्होंने उनसे बातचीत करने के लिए कहा और हमारे मिनिस्टर आफ कामर्स ने भी कई दफा उनको इन्वाइट किया है और मजदूरों से कहा कि आप लोग काम पर आ जाएं। यहां तक कि हमारी प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि काम शुरू हो जाए और जो भी बात करना चाहे, वह कर ले लेकिन दत्ता सामन्त ही दुनिया में सिर्फ एक लेबर लीडर हैं और ऐसा लगता है जैसे कि और कोई दूसरा लेबर लीडर हो ही नहीं सकता और सिर्फ उनसे ही बात करनी चाहिए। इस किस्म की जो बातें हुई हैं, वे ठीक नहीं है। इस किस्म की बातें करने की एक आदत-सी पड़ गई है और हमारे जो अपोजीशन के नेता हैं और जिनको 40-40 और 50-50 साल लेबर फील्ड में काम करते हो गए हैं, वे भी दत्ता सामन्त को अपना लीडर मान रहे हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इन सब लोगों के नेता बन गए हैं और विजयवाड़ा से लेकर काश्मीर तक उनके पीछे-पीछे फिरते हैं। इनका अब कोई बेस नहीं रहा है और जो भी पापूलर आदमी है और जो वह गड़बड़ करता है, उसके पीछे जाकर ये ताली बजाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस नमूने की पार्टी-पालीटिक्स नहीं चलनी चाहिए और मैं तो यह कहता हूं कि जो भी कदम आपने उठाया है, वह सही टाइम पर सही कदम उठाया है।

एक बात और कहनी है कि आपने मिलों से 40 लाख रुपया देने के लिए कहा है। आज मिलें ऐसी हैं, जो कि 20-20 लाख रुपया ही दे पाई हैं और इनका नेशनेलाइज़ेशन हुआ है। जो भी मुनासिब हो, वह आप कीजिए लेकिन जो आपके कानून हैं या आप की डाइरेक्शन हैं, उनका पालन करने में अगर दो-चार दिन की देर हुई है, तो उसको माफ कर दीजिए। इस वक्त जो कदम आपने उठाया है, उससे टेक्सटाइल मिलों और दूसरी जगहों पर आपके प्रति बड़ा भरोसा पैदा हो गया है।

आप जो कुछ करते हैं, वह अच्छे मन से करते हैं, देश की प्रगति के लिए करते हैं। इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will take up Half-Hour discussion.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Undertakings Bill has to be completed today itself so that we can send it to the other House tomorrow.

PROF. AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur) : We have already been sitting late in the evening for the last two days and it is not possible to sit late today also.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is an appeal from the Deputy Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : Many Hon. Members have already left the House thinking that it will be continued tomorrow. So, this can be postponed for tomorrow.

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North-East) : It can be taken up tomorrow.